Development of Bakery Industry

5663. SHRI ARUN SETHI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Society of Indian Bakers has suggested to the Planning Commission a ten year plan for the development of bakery industry for inclusion in the Fifth and Sixth Plans;

(b) if so, whether it has also suggested the setting up of a bakery research station to help the industry solve its technical problems relating to the use of various indigenous raw materials for baking; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) The Society of Indian Bakers has supported the suggestion of the Working Group on Agricultural Pricing, Marketing, Processing, Storage and Ware-housing appointed by the Ministry of Agriculture for the formulation of Fifth Five Year Plan to set up a Bakery Research Institute

(c) There are already National Institutes, like Central Food Technological Research Institute, Mysore, undertaking research in the development of bakery industry. Modern Bakeries (India) Ltd., a Government of India undertaking have also recently approved a proposal for opening a division in its set up for undertaking research in bakery In view of this, the proposal for setting up of a Bakery Research Institute, as recommended by the Working Group, was not included in the Fifth Plan programme.

Minimum needs programme in Orissa

5664. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the amount earmarked to be spent during the current financial year under the Minimum Needs Programme in the State of Orissa;

(b) the specific items selected for execution in each district of Orissa under the scheme; and

(c) whether Central Government have suggested any means to involve people at the grass roots to make planning a success?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). The overall size and the contents of the National Programme of Minimum Needs, which is an integral but distinct part of the State Annual Plan of Orissa for the current financial year, are in the process of being finalised in the light of the recent discussions held in the Planning Commission.

(c) The Central Government has always emphasised the need to insure public participation in the Process of Planning. This has been reiterated in the Draft Fifth Plan also. Attention is invited to paragraphs 9.184 to 9.187 on pages 115-116 of the Draft Fifth Five Year Plan (1974—79)—Volume I, copies of which have already been placed on the Table of the House.

राजस्थान में गांवों में बिजली उपलब्ध किया जाना

5665. श्री मूल चन्द डागा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी पचवर्षीय योजना में राजस्थान के कौन-कौन से जिलों के कितने-कितने ग्रामों में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने पांचवी योजनावधि के दौरान 6,000 गावों को विद्युतीकृत करने का अन्तिम कार्यक्रम बनाया है। अभी तक जिलेवार पृथक-पृथक ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता

5666. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार ने किस प्रकार की विदेशी सहायता कब से लेना बन्द कर दिया है, और

(ख) इस मामले में क्या प्रयास किये गये हैं तथा यह उद्देश्य कब तक प्राप्त हो जाएगा।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) सरकार ने विदेशी सहायता लेनी बन्द नहीं की है। आर्थिक स्वावलम्बन की प्राप्ति पांचवी योजना प्रारूप में निर्धारित महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। योजना में परिकल्पना की गई है कि 1978-79 के अन्त तक ऋण सेवा प्रभारों को छोड़ कर अन्य प्रकार की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं में से अधिकतम राशि की पूर्ति हमारे अपने संसाधनों में हो जायेगी। पांचवी जनयोजना प्रारूप में यह भी परिकल्पना की गई है कि 1985-86 तक, ऋण सेवा प्रभारों सहित हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं में से अधिकतम राशि की पूर्ति हम अपने संसाधनों से करने की स्थिति में होंगे और इस प्रकार रियायती सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहरहाल, यदि आवश्यक समझा गया तो सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर विदेशी पूंजी प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी। आन्तरिक उत्पादन में वृद्धिकर, निर्यात के लिए जोरदार और निरन्तर प्रयत्न कर और आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम द्वारा, स्वावलम्बन के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी है।

पाली जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

5667. श्री मूल चन्द डागा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में पाली जिले (राजस्थान) में कहां कहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए और आगामी पंचवर्षीय योजना में किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का क्या आधार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) तीन वर्ष की अवधि के दौरान यानी सन् 1971 से 1974 तक पाली जिले के निम्नलिखित स्थानों पर छह सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए हैं।

1. सिरियारी
2. कुशालपुरा
3. देवली
4. नियाज
5. बेरा
6. मुन्दरा